

VAID ICS LUCKNOW

यूपीएससी / यूपी पीसीएस

(करेंट अफेयर्स मैगज़ीन)

अक्टूबर, 2024



B-36, SECTOR-C, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

क्र सं.	टॉपिक	पृष्ठ सं.	क्रम सं.	टॉपिक	पृष्ठ सं.
1.	इंटरसेप्टेड मिसाइल सिस्टम	1		प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य	
2.	पीएम ई-ड्राइव योजना	3	1.	ग्रेन ग्रिफ़ गिरोह	41
3.	रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट	5	2.	अदिति 2.0 और DISC 12 पहल	41
4.	केंद्र की 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी	6	3.	2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार	42
5.	विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच 2024	8	4.	मात्सिगुएनका समुदाय	43
6.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	8	5.	ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन	44
7.	2024 का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार	10	6.	COFER	44
8.	ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड	12	7.	बिजनेस ईमेल समझौता	45
9.	राष्ट्रीय कृषि संहिता	13	8.	मूल खाते और किराए के खाते	45
10.	हरे धब्बे	15			
11.	21वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 10 सूत्री योजना	16			
12.	2024 का नोबेल शांति पुरस्कार	17			
13.	भारत यूनिसेफ का तीसरा सबसे बड़ा पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदाता	19			
14.	2024 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार	20			
15.	भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता: 2024	20			
16.	नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया	22			
17.	आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ)	23			
18.	ग्रीनवाशिंग दिशा-निर्देश	25			
19.	मिओम्बो वन	28			
20.	स्कैम से बचो अभियान	29			
21.	श्रम: वन स्टॉप सॉल्यूशन	30			
22.	ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-II	31			
23.	लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर	32			
24.	फ्लैग ऑफ कन्वीनिएस (FoC)	34			
25.	16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024	35			
26.	जैव विविधता अक्षुण्णता सूचकांक	37			
27.	सरको या 'सुसाइड पॉड'	39			

इंटरसेप्टेड मिसाइल सिस्टम/ आयरन डोम

चर्चा में क्यों? हाल ही में इजरायल ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा ईरान से आने वाली 180 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है।

इंटरसेप्टेड मिसाइल सिस्टम के बारे में:

इन्हें आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों या हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुँचने से पहले नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सिस्टम मिसाइल हमलों से बचाव के लिए देशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल रक्षा रणनीतियों के महत्वपूर्ण घटक हैं।

इंटरसेप्टेड मिसाइल सिस्टम के मुख्य प्रकार:

बूस्ट-फेज इंटरसेप्शन: ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को उसकी उड़ान के शुरुआती चरण (लॉन्च के बाद पहले कुछ मिनटों के भीतर) के दौरान नष्ट करने का प्रयास करते हैं। कम समय की अवधि के कारण इंटरसेप्शन के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है।

उदाहरण: एयरबोर्न लेजर (एबीएल) कार्यक्रम - संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित। इसमें बूस्ट चरण में मिसाइलों को नष्ट करने के लिए बोइंग 747 पर लगा एक लेजर सिस्टम शामिल था। हालाँकि, इस कार्यक्रम को अंततः रद्द कर दिया गया।

निर्देशित ऊर्जा हथियार - यू.एस. और चीन जैसे देश भविष्य के बूस्ट-फेज मिसाइल अवरोधन के लिए लेजर जैसे निर्देशित ऊर्जा हथियारों (डीईडब्ल्यू) पर काम कर रहे हैं।

मिडकोर्स-फेज अवरोधन:

ये सिस्टम मिडकोर्स चरण में मिसाइल को लक्षित करते हैं, जहाँ यह अंतरिक्ष में यात्रा करता है (बूस्ट चरण के बाद लेकिन वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने से पहले)।

उदाहरण:

ग्राउंड-बेस्ड मिडकोर्स डिफेंस (GMD) - संयुक्त राज्य अमेरिका। यह अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) को रोकने के लिए अलास्का और कैलिफ़ोर्निया में स्थित ग्राउंड-बेस्ड इंटरसेप्टर (GBI) का उपयोग करता है।

एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) - संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। यह समुद्र-आधारित प्रणाली मिडकोर्स चरण के दौरान अंतरिक्ष में मिसाइलों को रोकने के लिए SM-3 (स्टैंडर्ड मिसाइल-3) का उपयोग करती है।

S-500 प्रोमैटी - रूस। एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और यहाँ तक कि उपग्रहों को उनकी मिडकोर्स उड़ान के दौरान लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

टर्मिनल-फ्रेज़ इंटरसेप्शन:

- इस चरण में, इंटरसेप्टर मिसाइल को नष्ट कर देते हैं क्योंकि यह वायुमंडल में फिर से प्रवेश करती है और अपने लक्ष्य के पास पहुँचती है। टर्मिनल-फ्रेज़ सिस्टम अक्सर ज़मीन पर आधारित होते हैं और मध्यम और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे कम दूरी के खतरों से निपटते हैं।

उदाहरण:

- THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) - संयुक्त राज्य अमेरिका। THAAD उच्च ऊँचाई पर अपने टर्मिनल चरण के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है। इसे दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में तैनात किया गया है।
- S-400 ट्रायम्फ - रूस। एक बहुमुखी वायु रक्षा प्रणाली जो अपने टर्मिनल चरण में आने वाली मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। भारत ने भी S-400 खरीदा है।
- डेविड स्लिंग - इज़राइल। यह प्रणाली, इज़राइल की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा का हिस्सा है, जो टर्मिनल चरण में मध्यम दूरी के खतरों को रोकती है।

लेयर्ड मिसाइल डिफेंस:

- कुछ देशों ने अपनी उड़ान के विभिन्न चरणों में मिसाइलों को रोकने के लिए बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली विकसित की है, जो अधिक व्यापक सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के इंटरसेप्टर को जोड़ती है।

उदाहरण:

आयरन डोम - इज़राइल। आयरन डोम को टर्मिनल चरण में कम दूरी के रॉकेट और तोपखाने के गोले को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इज़राइल की बहु-परत रक्षा प्रणाली का हिस्सा है।

एरो मिसाइल सिस्टम - इज़राइल। एरो-2 और एरो-3 इज़राइल की बहु-परत प्रणाली का हिस्सा हैं, जो उच्च ऊँचाई पर और अंतरिक्ष में (मध्यम चरण) मध्यम से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

एजिस एशोर - जापान, रोमानिया (अमेरिकी सहयोग के साथ)। एजिस बीएमडी प्रणाली का एक भूमि-आधारित संस्करण, जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है।

एयर-बेस्ड इंटरसेप्टर: इन प्रणालियों में हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें शामिल होती हैं जो दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को रोकती हैं।

उदाहरण: पैट्रियट मिसाइल सिस्टम (PAC-3) - संयुक्त राज्य अमेरिका। सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई एक उन्नत वायु-रक्षा प्रणाली। इसे सऊदी अरब, इज़राइल और जर्मनी जैसे देशों में व्यापक रूप से तैनात किया गया है। बराक-8 - भारत और इज़राइल। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जिसे हवाई खतरों, जैसे विमान और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उन्नत अवरोधक मिसाइल प्रणालियों वाले प्रमुख देश:

संयुक्त राज्य अमेरिका:

- THAAD, GMD, एजिस BMD, पैट्रियट (PAC-3)।

रूस:

- S-400, S-500, A-135 मिसाइल रक्षा प्रणाली।

इज़राइल:

- आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो मिसाइल सिस्टम।

चीन:

- HQ-9 (S-300 के समान) और HQ-19 (मध्य मार्ग अवरोधन के लिए) जैसी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना।

भारत:

- बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) कार्यक्रम, S-400, बराक-8, और इज़राइल और अमेरिका के साथ अवरोधक मिसाइल प्रौद्योगिकी पर सहयोग।

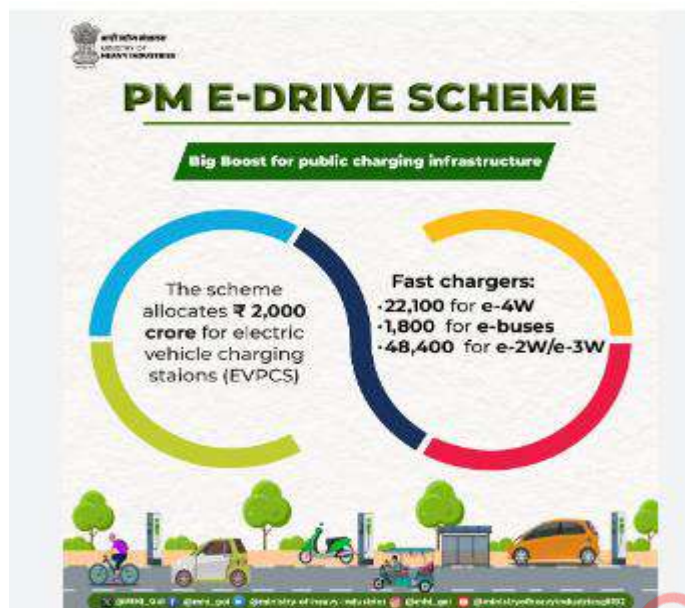
जापान:

- एजिस BMD, PAC-3, एजिस एशोर (अमेरिका के सहयोग से)।

पीएम ई-ड्राइव योजना

चर्चा में क्यों- सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और भारत में ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की है।

यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू की जाएगी।



मुख्य बिंदु:

सब्सिडी:

- पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे तय की गई है, लेकिन पहले वर्ष में कुल प्रोत्साहन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
- पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-टूव्हीलर्स, ई-थ्रीव्हीलर्स, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों को सहायता मिलेगी।
- ई-रिक्शा समेत तिपहिया वाहनों को पहले साल 25,000 रुपये की मांग प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसे दूसरे साल में आधा करके 12,500 रुपये कर दिया जाएगा।

ई-वाउचर:

- भारी उद्योग मंत्रालय इस योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर शुरू कर रहा है। ईवी की खरीद के समय, योजना पोर्टल खरीदार के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार करेगा।
- यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर ईवी खरीदारों की रेंज चिंता को दूर करती है। ये ईवीपीसीएस उच्च ईवी पैठ वाले चुनिंदा शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर भी स्थापित किए जाएंगे।
- इस योजना में ई-4डब्ल्यू के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और ई-2डब्ल्यू/3डब्ल्यू के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है। ईवीपीसीएस के लिए परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये होगा।

रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI)

चर्चा में क्यों? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक वित्तीय उपकरण है जो भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकताओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसे प्राकृतिक आपदाओं, कमोडिटी मूल्य झटकों या स्वास्थ्य महामारी जैसे बाहरी झटकों के कारण होने वाले आर्थिक संकटों के मामलों में पूर्ण आर्थिक सुधार कार्यक्रम की आवश्यकता के बिना त्वरित वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI) की मुख्य विशेषताएँ:

रैपिड डिस्बर्समेंट:

- RFI किसी देश की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना किसी लंबी बातचीत प्रक्रिया की आवश्यकता के धन के त्वरित वितरण की अनुमति देता है।
- यह उन देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं:

IMF के अन्य वित्तीय उपकरणों के विपरीत, जिनके लिए देशों को व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता होती है, RFI पूर्ण सुधार एजेंडे की मांग नहीं करता है। यह इसे उन स्थितियों के लिए आदर्श बनाता है जहाँ तत्काल सहायता महत्वपूर्ण है।

लचीली शर्तें:

हालांकि कुछ नीतियों और कार्रवाइयों को अभी भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन RFI में अन्य IMF ऋण साधनों की तुलना में कम शर्तें जुड़ी हुई हैं, जिससे प्राप्तकर्ता देश तत्काल स्थिरीकरण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

सीमाएँ:

- RFI के तहत कोई देश 12 महीने की अवधि के भीतर अपने IMF कोटे के 50% तक पहुँच सकता है। सटीक राशि देश की विशिष्ट वित्तपोषण आवश्यकताओं और उसके IMF कोटे के आकार के आधार पर निर्धारित की जाती है।

पात्रता:

- RFI सभी IMF सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई देश अचानक झटके या आपात स्थिति के कारण भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करता है।

पुनर्भुगतान शर्तें:

RFI के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता मानक IMF ब्याज दरों के साथ आती है, और देशों से 3.25 से 5 वर्षों के भीतर धनराशि चुकाने की अपेक्षा की जाती है।

RFI का उपयोग:

- COVID-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट के तत्काल आर्थिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए कई देशों द्वारा RFI का व्यापक उपयोग देखा। बांग्लादेश, नाइजीरिया और यूक्रेन जैसे देशों को अल्पकालिक भुगतान संतुलन की जरूरतों को पूरा करने के लिए RFI का समर्थन मिला।
- RFI का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं, जैसे तूफान और भूकंप की स्थितियों में भी किया गया है, ताकि अर्थव्यवस्थाओं को जल्दी से स्थिर किया जा सके।

अन्य IMF उपकरणों के साथ तुलना:

स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA) या एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) जैसे उपकरणों के विपरीत, जो भुगतान संतुलन के दीर्घकालिक मुद्दों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और जिनके लिए व्यापक बातचीत की आवश्यकता होती है, RFI सरल और तेज़ है।

- यह अल्पकालिक, आपातकालीन राहत के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि SBA और EFF अधिक दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरीकरण और सुधारों के लिए अभिप्रेत हैं।

केंद्र ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी दी: शास्त्रीय भाषा क्या है?

चर्चा में क्यों? हाल ही में, केंद्र द्वारा पांच भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें यह भी कहा गया कि सरकार "उनकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने" के लिए काम कर रही है।

- 5 भाषाओं: **मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली** को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी गई है...
- इनमें से कुछ भाषाएँ एक दशक से शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में मराठी को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था।
- 2014 में, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भाषा का मूल्यांकन करने के लिए भाषा विशेषज्ञों की एक समिति बनाई। केंद्र को पैनल की रिपोर्ट मिली, जिसने सत्यापित किया कि मराठी शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- **तमिल (2004), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013) और ओडिया (2014)** सहित छह भाषाएँ पहले से ही भारत में "शास्त्रीय" की उपाधि धारण कर रही हैं।

- सभी शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। तो, भारत की शास्त्रीय भाषा क्या है और इसका क्या महत्व है?

भारत की शास्त्रीय भाषा क्या है?

- "भारतीय शास्त्रीय भाषाएँ" या "सम्मोड़ी" शब्द उन भाषाओं के समूह को संदर्भित करता है जिनका एक लंबा इतिहास और एक समृद्ध, अद्वितीय और विशिष्ट साहित्यिक विरासत है। ग्यारह भाषाओं को भारत गणराज्य द्वारा भारत की शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारत सरकार ने 2004 में घोषणा की कि भाषाएँ भारत की "शास्त्रीय भाषा" की उपाधि धारण कर सकती हैं यदि वे कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इसकी स्थापना भाषाई विशेषज्ञों की समिति और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय के रूप में नामित करने के अनुरोधों की जाँच करने के लिए एक समिति की स्थापना की।

भारत की शास्त्रीय भाषा का क्या महत्व है?

- 1 नवंबर, 2004 को जारी भारत सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, "शास्त्रीय भाषा" के रूप में नामित भाषा का निम्नलिखित महत्व होगा:
- हर साल, शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों को दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।
- शास्त्रीय भाषा अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए शास्त्रीय भाषाओं के लिए व्यावसायिक पीठों की एक विशिष्ट संख्या स्थापित करने के लिए कहा जाएगा, जिसकी शुरुआत कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में की जाएगी।

भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड क्या हैं?

संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, शास्त्रीय भाषा मानदंड:

- भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ या प्रलेखित इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराने होने चाहिए।
- भाषा में प्राचीन साहित्य या ग्रंथ होने चाहिए जिन्हें इसके वक्ता अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में महत्व देते हों।
- भाषा की साहित्यिक विरासत मूल होनी चाहिए और किसी अन्य भाषण समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए।
- शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या व्युत्पत्तियों के बीच एक संभावित असातत्य होना चाहिए, और शास्त्रीय भाषा और साहित्य अपने आधुनिक रूप से अलग होना चाहिए।

विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच 2024

चर्चा में क्यों- हाल ही में दुबई में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किया गया, जिसमें वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ लाया गया।

इस मंच का विषय था, "वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना: अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना"।

सत्र के मुख्य बिंदु:

- ऊर्जा-गहन और कठिन-से-कम करने वाले उद्योगों को डीकार्बोनाइज़ करना" शीर्षक वाले एक प्रमुख सत्र में भारी परिवहन, निर्माण, ऊर्जा और रसायन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की रणनीतियों की खोज की गई।
- 4Ps: PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी + परोपकारी) में एक और 'P' जोड़ना," ने प्रभावी जलवायु समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए परोपकारियों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।
- सत्र में एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा की गई।
- हम एक स्थायी भविष्य बनाने में मदद करने के लिए AI का उपयोग कैसे कर सकते हैं?"

संधारणीय विमानन ईंधन (एसएएफ) का भविष्य:

- पैनलिस्टों ने 2050 तक एसएएफ उत्पादन को मौजूदा 200,000 टन से बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर चर्चा की। उन्होंने एसएएफ उत्पादन के लिए विभिन्न सीओ2 स्रोतों की भी खोज की और हितधारक सहयोग और पूंजी निवेश के महत्व पर जोर दिया।
- यूएई सरकार के 2031 तक 1% एसएएफ उपयोग के लक्ष्य को क्षेत्र में बदलाव के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में देखा गया।
- फोरम ने दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रगति को आगे बढ़ाने में उनके महत्व को पहचानते हुए एक संधारणीय भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई)/कृषोन्ति योजना (केवाई)

चर्चा में क्यों ? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए कृषोन्ति योजना (केवाई) को मंजूरी दी

राज्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धन का पुनर्वितरण करने की सुविधा दी गई

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के बारे में:

- पीएम-आरकेवीवाई टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी, केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करेगी। सभी घटक विभिन्न घटकों के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्ति योजना (केवाई) को 1,01,321.61 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। इन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है।
- यह अभ्यास सभी मौजूदा योजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करता है। जहां भी किसानों के कल्याण के लिए किसी क्षेत्र को बढ़ावा देना आवश्यक समझा गया है, वहां योजना को मिशन मोड में लिया गया है। उदाहरण के लिए, **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम [एनएमईओ-ओपी], स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, डिजिटल कृषि** और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन बीज [एनएमईओ-ओएस]।
- केवाई के तहत एक घटक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना को एक अतिरिक्त घटक अर्थात् एमओवीसीडीएनईआर - **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट** (एमओवीसीडीएनईआर-डीपीआर) जोड़कर संशोधित किया जा रहा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए ताकत प्रदान करेगा।
- इन योजनाओं के युक्तिकरण से राज्यों को राज्य के कृषि क्षेत्र से संबंधित एक समग्र रणनीतिक दस्तावेज तैयार करने का अवसर मिलता है। यह रणनीतिक दस्तावेज न केवल फसलों के उत्पादन और उत्पादकता पर केंद्रित है, बल्कि जलवायु अनुकूल कृषि के विकास और कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण से संबंधित उभरते मुद्दों को भी संबोधित करता है।
- इन योजनाओं की परिकल्पना रणनीतिक ढांचे के उद्देश्यों से संबंधित समग्र रणनीति और **योजनाओं/कार्यक्रमों** को स्पष्ट करने के लिए की गई है।
- कुल प्रस्तावित व्यय में से 1.5 करोड़ रुपये का व्यय पूर्वोत्तर राज्यों को किया जाएगा। 1,01,321.61 करोड़ रुपये में से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएंडएफडब्ल्यू) के केंद्रीय हिस्से का अनुमानित व्यय 69,088.98 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 32,232.63 करोड़ रुपये है। इसमें आरकेवीवाई के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये और केवाई के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये शामिल हैं।

पीएम-आरकेवीवाई में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:

- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
- कृषि वानिकी

- परंपरागत कृषि विकास योजना
- फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण
- प्रति बूंद अधिक फसल
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम
- आरकेवीवाई डीपीआर घटक
- कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरक निधि

माइक्रोआरएनए की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार

चर्चा में क्यों? मैसाचुसेट्स चैन मेडिकल स्कूल के शोधकर्ता विक्टर एम्ब्रोस और मैसाचुसेट्स अस्पताल के आणविक जीवविज्ञानी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर गैरी रुवकुन को माइक्रोआरएनए की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया।

माइक्रोआरएनए कोशिका के कार्य में बहुत हद तक शामिल होता है।

माइक्रोआरएनए और कोशिका विकास में इसका महत्व:

- यह जीवों के विकास और कार्य करने के तरीके के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा।
- माइक्रोआरएनए के साथ एम्ब्रोस और रुवकुन का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों को कैंसर या मिर्गी जैसी बीमारियों का इलाज करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह खोज कोशिकाओं के विकास से संबंधित है।

डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड):

संरचना: डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना एक डबल-स्ट्रैंडेड अणु है, जिसमें फॉस्फेट समूह, एक शर्करा (डीऑक्सीराइबोज) और नाइट्रोजनस बेस (एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन) शामिल हैं।

कार्य: डीएनए एक जीव की आनुवंशिक जानकारी संग्रहीत करता है और वंशानुगत लक्षणों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशों को एनकोड करता है और सेलुलर गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

स्थान: मुख्य रूप से कोशिका नाभिक (यूकेरियोटिक कोशिकाओं में) में पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया (माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए) में भी पाया जाता है।

2. आरएनए (राइबोन्यूक्लिक एसिड):

संरचना: आरएनए आम तौर पर सिंगल-स्ट्रैंडेड होता है और न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जिसमें एक शर्करा (राइबोज), फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनस बेस (एडेनिन, यूरैसिल, गुआनिन और साइटोसिन) होते हैं।

कार्य: आरएनए डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण के बीच एक संदेशवाहक और मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह डीएनए (नाभिक में) से आनुवंशिक कोड को कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित करने में शामिल है, जहाँ प्रोटीन संश्लेषित होते हैं।

प्रकार: कोशिका में कई प्रकार के आरएनए अलग-अलग भूमिकाएँ निभाते हैं:

- मैसेंजर आरएनए (एमआरएनए)
- ट्रांसफर आरएनए (टीआरएनए)
- राइबोसोमल आरएनए (आरआरएनए)
- माइक्रो आरएनए (एमआईआरएनए)

3. मैसेंजर आरएनए (एमआरएनए):

भूमिका: एमआरएनए प्रतिलेखन के दौरान संश्लेषित होता है, जहाँ डीएनए के एक खंड को एमआरएनए में कॉपी किया जाता है। यह नाभिक में डीएनए से आनुवंशिक जानकारी को कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक ले जाता है, जहाँ प्रोटीन संश्लेषित होते हैं (अनुवाद)।

प्रक्रिया:

प्रतिलेखन: नाभिक में डीएनए से एमआरएनए का उत्पादन होता है।

अनुवाद: राइबोसोम एमिनो एसिड को प्रोटीन में इकट्ठा करने के लिए कोडन (न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपल) में एमआरएनए अनुक्रम को पढ़ता है।

महत्व: प्रोटीन संश्लेषण में एमआरएनए महत्वपूर्ण है। हाल के विकासों में, mRNA तकनीक का उपयोग टीकों (जैसे, COVID-19 टीके) में किया गया है ताकि कोशिकाओं को एक प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश दिया जा सके जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है।

4. माइक्रोआरएनए (miRNA):

भूमिका: miRNA एक छोटा, गैर-कोडिंग RNA अणु (लगभग 21-25 न्यूक्लियोटाइड) है जो पोस्ट-ट्रांसक्रिप्शनल स्तर पर जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है।

तंत्र: miRNAs लक्ष्य mRNA पर पूरक अनुक्रमों से बंधते हैं, जिससे mRNA का क्षरण या अनुवाद का अवरोध होता है, इस प्रकार उत्पादित प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करता है।

कार्य:

miRNAs विकासात्मक प्रक्रियाओं, कोशिका विभेदन, एपॉप्टोसिस और रोगों (जैसे, कैंसर, हृदय रोग) में शामिल विभिन्न जीनों के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वे जीन अभिव्यक्ति नियामकों के रूप में कार्य करते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण को ठीक करने और कोशिकाओं में होमोस्टैसिस बनाए रखने में योगदान करते हैं।

ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड

चर्चा में क्यों- ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड ने हाल ही में अपनी पहली परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य रसायनों और अपशिष्टों का सुरक्षित और संधारणीय प्रबंधन है।

ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स के बारे में:

ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स - केमिकल्स और अपशिष्टों से होने वाले नुकसान से मुक्त ग्रह (GFC) के लिए, एक ऐसे भविष्य के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है जिसमें मानवता रसायनों से सुरक्षित और संधारणीय तरीके से लाभ उठा सके, जबकि उनके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके।

- सितंबर 2023 में पांचवें अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन सम्मेलन (ICCM5) में अपनाए गए फ्रेमवर्क का उद्देश्य ग्रह और मानव स्वास्थ्य दोनों की रक्षा करना है, मजबूत शासन तंत्र की वकालत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करना है।
- फ्रेमवर्क में उत्पादों और अपशिष्टों सहित रसायनों के जीवनचक्र को संयुक्त रूप से संबोधित करने में देशों और हितधारकों का मार्गदर्शन करने के लिए पाँच रणनीतिक उद्देश्यों और 28 लक्ष्यों के साथ एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई है।
- यह अनूठा बहु-हितधारक समझौता सरकारों, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी और अंतर-सरकारी संगठनों, युवाओं और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करता है।

कार्यकारी बोर्ड परिचालन संबंधी निर्णय लेता है और कोष के कामकाज की देखरेख करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र के 2 राष्ट्रीय प्रतिनिधि
- सभी दाताओं और योगदानकर्ताओं के प्रतिनिधि।

वित्तपोषण: कोष तीन साल तक की कार्यान्वयन अवधि के लिए 300,000 से 800,000 अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- जीएफसी कोष के लिए धन स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- यह बॉन घोषणा द्वारा समर्थित है, एक उच्च-स्तरीय घोषणा जिस पर बॉन, जर्मनी में ICCM5 में भी सहमति हुई थी।

राष्ट्रीय कृषि संहिता

चर्चा में क्यों? भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मौजूदा राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि संहिता (NAC) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय कृषि संहिता क्या है?

- BIS एक राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करता है। कृषि में, इसने पहले से ही मशीनरी (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, आदि) और विभिन्न इनपुट (उर्वरक, कीटनाशक, आदि) के लिए मानक निर्धारित कर दिए हैं।
- हालाँकि, अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो BIS मानकों के दायरे में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए, खेतों की तैयारी, सूक्ष्म सिंचाई और पानी के उपयोग जैसी कृषि प्रथाओं के लिए कोई मानक नहीं है। इस प्रकार, लंबे समय से नीति निर्माताओं को एक व्यापक मानक ढाँचे की आवश्यकता महसूस हुई है, जैसा कि अब BIS द्वारा तैयार किया जा रहा है।
- NAC पूरे कृषि चक्र को कवर करेगा, और इसमें भविष्य के मानकीकरण के लिए एक मार्गदर्शन नोट भी होगा।

कोड के दो भाग होंगे। पहले में सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत होंगे, और दूसरे में धान, गेहूँ, तिलहन और दलहन जैसी फसलों के लिए फसल-विशिष्ट मानकों से संबंधित होगा। एनएसी किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और क्षेत्र में शामिल अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

एनएसी क्या कवर करेगा?

- कृषि मशीनरी के मानकों के अलावा, एनएसी सभी कृषि प्रक्रियाओं और कटाई के बाद के कार्यों को कवर करेगा, जैसे कि फसल का चयन, भूमि की तैयारी, बुवाई/रोपाई, सिंचाई/जल निकासी, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन, कटाई/थ्रेसिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण, कटाई के बाद, स्थिरता और रिकॉर्ड रखरखाव।
- इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के उपयोग जैसे इनपुट प्रबंधन के लिए मानक, साथ ही फसल भंडारण और ट्रेसेबिलिटी के लिए मानक भी शामिल होंगे।
- महत्वपूर्ण रूप से, एनएसी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती जैसे सभी नए और उभरते क्षेत्रों के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स के उपयोग को भी कवर करेगा।

राष्ट्रीय कृषि संहिता के घोषित उद्देश्य क्या हैं?

- कृषि जलवायु क्षेत्रों, फसल के प्रकार, देश की सामाजिक आर्थिक विविधता और कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कृषि प्रथाओं के लिए सिफारिशों को शामिल करने वाला एक कार्यान्वयन योग्य राष्ट्रीय कोड बनाना;
- **नीति निर्माताओं, कृषि विभागों और नियामकों** को उनकी योजनाओं, नीतियों या विनियमों में एनएसी के प्रावधानों को शामिल करने के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करके भारतीय कृषि में गुणवत्ता संस्कृति को सक्षम करने वाले के रूप में कार्य करना;
- **कृषि प्रथाओं में प्रभावी निर्णय** लेने को सुनिश्चित करने के लिए कृषक समुदाय के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका बनाना;
- अनुशासित कृषि प्रथाओं के साथ प्रासंगिक भारतीय मानकों को एकीकृत करना।
- स्मार्ट खेती, स्थिरता, पता लगाने और दस्तावेज़ीकरण जैसे कृषि के क्षेत्रीय पहलुओं को संबोधित करना; और
- कृषि विस्तार सेवाओं और नागरिक समाज संगठनों द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहायता करना।

इस परियोजना के लिए प्रस्तावित समयरेखा क्या है?

- बीआईएस ने प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए पहले ही एक रणनीति तैयार कर ली है। इसने 12-14 विशेष रूप से पहचाने गए क्षेत्रों के लिए कार्य पैनल बनाए हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और आरएंडडी संगठन शामिल होंगे। ये पैनल कोड का मसौदा तैयार करेंगे, जिसके लिए एनएसी की संभावित समयसीमा अक्टूबर 2025 तक की गई है।

मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म क्या हैं? वे कैसे महत्वपूर्ण हैं?

- एनएसी का मसौदा तैयार करने के अलावा, बीआईएस ने देश के चुनिंदा कृषि संस्थानों में 'मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म' (एसएडीएफ) स्थापित करने की पहल भी की है।
- बीआईएस के अनुसार, ये फार्म भारतीय मानकों के अनुसार विभिन्न कृषि पद्धतियों और नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिक स्थल के रूप में काम करेंगे।
- बीआईएस इन संस्थानों को एसएडीएफ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जहां विस्तार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी, किसान या उद्योग के लोग सहित कोई भी आकर सीख सकता है।

हरे धब्बे (ग्रीन पैचेज)

चर्चा में क्यों- अंटार्कटिका में हरे धब्बे की खोज एक हालिया घटना है जिसने वैज्ञानिक रुचि और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को जन्म दिया है। ये धब्बे मुख्य रूप से अंटार्कटिक क्षेत्र में उगने वाले शैवाल के खिलने वाले क्षेत्र हैं, जिन्हें हाल के वर्षों में अधिक बार देखा गया है।

ये हरे धब्बे क्या हैं?

- अंटार्कटिका में देखे गए हरे धब्बे शैवाल के खिलने वाले हैं - विशेष रूप से सूक्ष्म पौधे, जैसे कि बर्फ के शैवाल - जो पिघलती बर्फ और बर्फ में पनपते हैं।
- ये शैवाल चरम स्थितियों में जीवित रह सकते हैं और आमतौर पर गर्मियों के महीनों में खिलते हैं जब तापमान बढ़ता है, और बर्फ पिघलना शुरू होती है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं, और कुछ मामलों में, **लाल शैवाल** भी दिखाई देते हैं, जिससे "**लाल बर्फ**" या "**तरबूज बर्फ**" बनती है।

अंटार्कटिका में हरे धब्बे के कारण:

तापमान में वृद्धि:

- जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में तापमान में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से इसके तटों और अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर, जो ग्रह पर सबसे तेजी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में से एक है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, बर्फ पिघलती है, जिससे शैवाल के पनपने के लिए उपयुक्त नम वातावरण बनता है।

बर्फ पिघलने में वृद्धि:

- बर्फ पिघलने की अधिक लगातार और लंबी अवधि शैवाल के बढ़ने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनाती हैं। पिघला हुआ पानी शैवाल के लिए एक आवास प्रदान करता है, जिससे वे बड़े क्षेत्रों में फैल सकते हैं।

पोषक तत्वों की उपलब्धता:

- हवा और समुद्री धाराओं द्वारा ले जाए जाने वाले पोषक तत्व, साथ ही पक्षियों और जानवरों की बूंदों (जैसे पेंगुइन और सील की बूंदें), नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके शैवाल के प्रसार में योगदान करते हैं।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:

अल्बेडो प्रभाव पर प्रभाव:

- सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक यह है कि शैवाल के खिलने से बर्फ और बर्फ की सतहों की अल्बेडो (परावर्तकता) कम हो जाती है। बर्फ और बर्फ आम तौर पर सूर्य के प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करते हैं, जिससे पृथ्वी

के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हालाँकि, गहरे हरे रंग के पैच अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, जिससे बर्फ और बर्फ और अधिक पिघलती है, जो बदले में गर्मी को तेज करती है और एक फीडबैक लूप बनाती है।

पारिस्थितिक असंतुलन:

- शैवाल का तेजी से प्रसार अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है, जो परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। जबकि कुछ प्रजातियों को शैवाल (जैसे कुछ सूक्ष्मजीव) में वृद्धि से लाभ हो सकता है, यह उन अन्य प्रजातियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है जो विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर हैं।

ग्लोबल वार्मिंग का संकेतक:

- हरे धब्बों का दिखना अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग के चल रहे प्रभाव का एक स्पष्ट संकेत है। यह क्षेत्र पहले से ही तापमान, बर्फ के आवरण और जैव विविधता में बदलाव का अनुभव कर रहा है, और शैवाल की वृद्धि इस बात के कई संकेतकों में से एक है कि ध्रुवीय पर्यावरण कैसे बदल रहा है।

विस्तारित आवासों की संभावना:

- जैसे-जैसे अंटार्कटिका गर्म होता है, यह अधिक जटिल पौधों और सूक्ष्मजीवों के पनपने के लिए परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है, जो संभावित रूप से महाद्वीप के परिदृश्य के कुछ हिस्सों को बदल सकता है। इससे उन क्षेत्रों में नए पारिस्थितिकी तंत्रों का उदय हो सकता है जो पहले अत्यधिक ठंड के कारण दुर्गम थे।

वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि:

अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना, शैवाल के खिलने के गर्म होने के प्रभाव से बढ़ जाता है, जो वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि में योगदान देता है। समुद्र के स्तर में छोटी-सी वृद्धि भी दुनिया भर के तटीय समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है, जिससे बाढ़ और तूफान की आवृत्ति बढ़ जाती है।

21वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 10 सूत्री योजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दशक में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार दोगुना होकर अब 130 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि 21वीं सदी, जिसे एशियाई सदी भी कहा जाता है, भारत की और आसियान देशों की सदी है। आसियान देशों में मलेशिया, थाइलैंड, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस और सिंगापुर शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री योजना की घोषणा की।

10 सूत्री योजना की घोषणा-

1. 2025 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना। इसके लिए भारत संयुक्त गतिविधियों के लिए पांच मिलियन अमरीकी डॉलर उपलब्ध कराएगा
2. युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्ट-अप महोत्सव, हैकाथॉन, संगीत महोत्सव, आसियान-भारत थिंक टैंक नेटवर्क और दिल्ली वार्ता सहित कई केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से एक्ट-ईस्ट नीति के एक दशक का उत्सव मनाना
3. आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत आसियान-भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करना
4. नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या को दोगुना करना, भारत में कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिए नए अनुदान प्रदान करना
5. 2025 तक आसियान-भारत माल व्यापार समझौते की समीक्षा
6. भारत आपदाओं से निपटने के लिए 50 लाख डॉलर उपलब्ध कराएगा
7. स्वास्थ्य की दिशा में स्वास्थ्य मंत्रियों का एक नया ट्रैक शुरू करना
8. डिजिटल और साइबर नीति मजबूत करने की दिशा में आसियान-भारत साइबर नीति वार्ता का एक नियमित तंत्र शुरू करना
9. ग्रीन हाइड्रोजन पर कार्यशाला
10. जलवायु पुनरुत्थान की दिशा में 'मां' के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान में शामिल होने के लिए आसियान नेताओं को आमंत्रित करना।

पीएम मोदी ने डिजिटल भविष्य के लिए आसियान इंडिया फंड की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आसियान और भारत के बीच वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। उन्होंने आसियान थिंक टैंक ईआरआईए के लिए भी समर्थन व्यक्त किया जो आसियान-भारत संबंधों को गहरा करेगा।

निहोन हिडानक्यो को मिला 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार

चर्चा में क्यों- नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना है।

- नॉर्वेजियन समिति ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने और परमाणु हथियारों के पीड़ितों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के अपने प्रयासों के लिए निहोन हिडानक्यो संगठन को चुना कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया जाना चाहिए।

- निहोन हिडानक्यो संगठन को 10 दिसंबर 2024 को ओस्लो, नॉर्वे में एक समारोह में 11 मिलियन क्रोनर पुरस्कार प्राप्त होगा। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। वहीं, **ओस्लो.नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया जाता है।**

निहोन हिडानक्यो के बारे में-

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, संयुक्त राज्य अमरीका के वायु सेना ने जापान पर दो परमाणु बम गिराए। हमले में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और बचे लोगों को परमाणु विकिरण का असर झेलना पड़ा।
- परमाणु युद्ध के विभीषिका के खिलाफ हिरोशिमा और नागासाकी में एक शक्तिशाली स्थानीय जमीनी स्तर पर परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन उभरा, जिसे लोकप्रिय रूप से हिबाकुशा (हिरोशिमा और नागासाकी का संयोजन) कहा जाता है।
- 1956 में, स्थानीय हिबाकुशा एसोसिएशन ने, प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियार परीक्षण के पीड़ितों के साथ मिलकर एक नए संघटन ए- और एच-बम पीड़ित संगठनों का जापान परिसंघ का गठन किया।
- **जापानी भाषा में संक्षेप में इसे निहोन हिडानक्यो नाम दिया गया। निहोन जापान का जापानी नाम है।**

नोबेल शांति पुरस्कार -

- नोबेल फाउंडेशन ने अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार, 1900 में नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना की और पहला शांति पुरस्कार 1901 में दिया गया।
- पहला पुरस्कार संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी डनट और फ्रांस के फ्रेडरिक पैसी द्वारा साझा किया गया था।
- 2023 में, यह पुरस्कार ईरानी शांति कार्यकर्ता नर्गिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया।

भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता-

- **मदर टेरेसा 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक थीं।** उन्होंने कोलकाता (तब कलकत्ता) में गरीबों और निराश्रितों की देखभाल के लिए अपना संगठन, "द मिशनरीज ऑफ चैरिटी" शुरू किया था।
- **2014 में, कैलाश सत्यार्थी** ने पाकिस्तान की माला यूसुफजई के साथ शांति पुरस्कार साझा किया। कैलाश भारत में बाल श्रम के उन्मूलन और बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए स्थापित "बचपन बचाओ आंदोलन" के संस्थापक हैं।

भारत बना यूनिसेफ का तीसरा सबसे बड़ा पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदाता

- भारतीय व्यवसायों ने 2016 से 2023 तक यूनिसेफ को उसके वैश्विक कार्य के लिए लगभग 6 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की, जिससे यह 2023 में तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया।
- इस योगदान में टीके, फार्मास्यूटिकल्स और पोषण आपूर्ति शामिल हैं जो दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के लिए जीवन रक्षक वस्तुओं और सेवाओं के भारतीय आपूर्तिकर्ता वैश्विक स्तर पर बच्चों के लिए यूनिसेफ के काम के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- भारत सरकार के साथ दीर्घकालिक साझेदारी देश में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक रही है। यूनिसेफ इन योगदानों को महत्व देता है, जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सबसे कमजोर बच्चों के जीवन को बचाने के यूनिसेफ के मिशन की प्राथमिकता है।
- यूनिसेफ भारत स्थित आपूर्तिकर्ताओं से बच्चों के टीकाकरण, स्वास्थ्य और पोषण उत्पादों की उल्लेखनीय मात्रा खरीदता है जो यूनिसेफ के वैश्विक विकास और मानवीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यूनिसेफ के आपूर्ति प्रभाग की निदेशक लीला पक्काला की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा-

- हाल ही में यूनिसेफ के आपूर्ति प्रभाग की निदेशक लीला पक्काला ने भारत के साथ यूनिसेफ की वैश्विक आपूर्ति साझेदारी को बनाए रखने और विस्तारित करने हेतु प्रमुख हितधारकों से मुलाकात की। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब यूनिसेफ भारत सरकार के साथ अपनी उपस्थिति और निरंतर साझेदारी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है।
- सुश्री पक्काला की यात्रा भारत के साथ यूनिसेफ की वैश्विक आपूर्ति साझेदारी के महत्व और दुनिया भर में बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गहन सहयोग की महान क्षमता को उजागर करती है।
- राष्ट्रीय नीतियों और सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए, यूनिसेफ भारतीय बाजार को आकार देने में योगदान देता है ताकि उनकी आपूर्ति श्रृंखलाएं सतत व्यावसायिक प्रथाओं के साथ संरेखित हों और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे।

यूनिसेफ के बारे में-

- यूनिसेफ, बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है, खासकर सबसे वंचित बच्चों और सबसे दुर्गम स्थानों पर। यह 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में बच्चों को जीवित रहने, पनपने और उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता है।
- यूनिसेफ इंडिया भारत में सभी लड़कियों और लड़कों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, जल और स्वच्छता, शिक्षा, सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा तथा बाल संरक्षण कार्यक्रमों को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए व्यवसायों और व्यक्तियों से प्राप्त समर्थन और दान पर निर्भर करता है।

- यूनिसेफ का आपूर्ति और रसद मुख्यालय - यूनिसेफ आपूर्ति प्रभाग कोपेनहेगन, डेनमार्क में स्थित है। यूनिसेफ की आपूर्ति दुनिया के सबसे कमजोर बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार: 2024/ राष्ट्र असफल या सफल क्यों होते हैं?

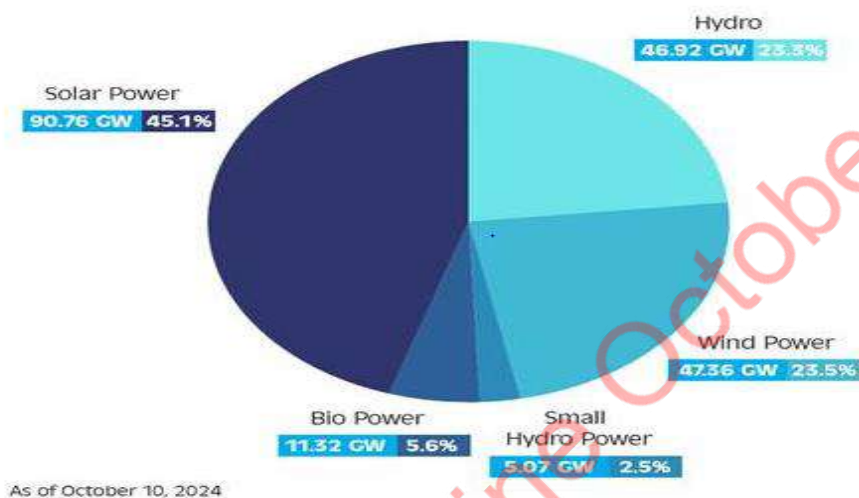
2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डारोन ऐसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए. रॉबिन्सन को उनके शोध के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि संस्थागत अंतर किसी देश की समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं। उनका काम इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति - विशेष रूप से, चाहे वे समावेशी हों या शोषक - यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कुछ देश आर्थिक रूप से क्यों समृद्ध होते हैं जबकि अन्य नहीं।

- पुरस्कार विजेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि **समावेशी संस्थाएँ**, जो लोकतंत्र, कानून के शासन और न्यायसंगत आर्थिक नीतियों का समर्थन करती हैं, समृद्धि को बढ़ावा देती हैं।
- इसके विपरीत, **शोषक संस्थाएँ अक्सर संसाधनों** का दोहन करती हैं और विकास को बाधित करती हैं, जिससे एक ऐसा चक्र बनता है जहाँ व्यापक आबादी की कीमत पर अभिजात वर्ग को लाभ होता है। उनके निष्कर्ष ऐतिहासिक उदाहरणों, विशेष रूप से उपनिवेशीकरण के प्रभावों पर आधारित हैं, जहाँ **समावेशी या शोषक प्रणालियों** की स्थापना ने पूर्व उपनिवेशों पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला था।
- शोध वैश्विक स्तर पर देखी गई तीव्र आर्थिक असमानताओं को भी संबोधित करता है, जहाँ सबसे अमीर **20% देश** सबसे गरीब **20% देशों की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक अमीर** हैं। ऐसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि यह समझने में मदद करती है कि कई राष्ट्र आर्थिक विकास हासिल करने में क्यों विफल होते हैं।

भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता: 2024

चर्चा में क्यों ? भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 10 अक्टूबर, 2024 तक **200 गीगावाट** (गीगावाट) के आंकड़े को पार कर गई है। यह देश की कुल स्थापित क्षमता का 46.3 प्रतिशत है।

Renewable Energy Capacity in India



भारत के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य:

- 2030 तक: गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित बिजली क्षमता हासिल करना।
- 2070 तक नेट-जीरो: COP26 में भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुसार।

States Driving India's Renewable Energy Capacity



Present status of renewable energy in India (as of October 2024):

Category	Installed Capacity (GW)	Contribution (%)
Solar Power	90.76 GW	20.03%
Wind Power	47.36 GW	10.46%
Large Hydro	46.92 GW	10.36%
Small Hydro	5.07 GW	1.12%
Bio Power	11.32 GW	2.50%
Total Renewable	201.45 GW	46.30%
Total Installed Capacity	432.69 GW	

नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के लिए अपने सबसे महत्वाकांक्षी ग्रहीय मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य सौर मंडल के सबसे दिलचस्प महासागरीय दुनिया में जीवन की संभावना का पता लगाना है। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण 14 अक्टूबर, 2024 को किया गया।

- अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा में नासा के केंनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन हेवी रॉकेट पर लॉन्च किया जाना है। यह नासा द्वारा किसी भी ग्रहीय मिशन के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है।
- कथित तौर पर, सौर सरणियों के विस्तार के साथ, यह एक बास्केटबॉल कोर्ट (100 फीट, या 30.5 मीटर, टिप से टिप) तक फैला हुआ है। यूरोपा अंतरिक्ष यान की यात्रा सीधी नहीं बल्कि लंबी होगी, यानी 1.8 बिलियन मील (2.9 बिलियन किलोमीटर) क्योंकि यूरोपा क्लिपर मंगल और फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगा, गति प्राप्त करेगा।
- मिशन के पास अब से 6 नवंबर तक दो संभावित लॉन्च विंडो हैं। नासा को सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों अवसर तात्कालिक हैं क्योंकि प्रतिदिन केवल एक सटीक समय होता है जब लॉन्च हो सकता है। 5 अक्टूबर को यूरोपा क्लिपर को लॉन्च करने की योजना तूफान मिल्टन के प्रभावों के कारण विलंबित हो गई।

यूरोपा क्लिपर क्या करेगा?

- 5 बिलियन डॉलर के इस मिशन का उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे संभावित जीवन की जांच करना है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, यूरोपा में एक विशाल उपसतह महासागर है जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों से अधिक पानी है जो कि अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख लक्ष्य है।

यूरोपा क्लिपर जूनो और जूस में शामिल होगा:

- बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले पहले से ही दो अंतरिक्ष यान हैं: नासा का जूनो जुलाई 2016 से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है और ईएसए का ज्यूपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर (जूइस) अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया।
- यूरोपा क्लिपर मिशनों की तिकड़ी को पूरा करेगा, और उम्मीद है कि यह अप्रैल 2030 में बृहस्पति पर पहुंचेगा, जो अलग-अलग प्रक्षेप पथों के कारण अपने गंतव्य पर जूस से लगभग एक वर्ष पहले पहुंच जाएगा।

आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ)

आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें न केवल दस आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ) सदस्य देश शामिल हैं, बल्कि कई प्रमुख गैर-आसियान देश भी शामिल हैं जो क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण हितधारक हैं।

इतिहास और गठन:

- **एआरएफ की स्थापना** 1994 में बैंकॉक, थाईलैंड में 26वीं आसियान मंत्रिस्तरीय बैठक (एएमएम) के दौरान की गई थी।

• इसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया था, जो राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए एक बहुपक्षीय सेटिंग प्रदान करता है।

सदस्यता:

- ARF में 27 सदस्य हैं: 10 आसियान सदस्य देश और 17 अन्य प्रतिभागी, जिनमें निम्नलिखित देश शामिल हैं:
- भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया
- रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, और अन्य।
- भारत 1996 से इसका सदस्य है।

विस्तारित आसियान समुद्री मंच (EAMF):

• विस्तारित आसियान समुद्री मंच (EAMF) एक ऐसा मंच है जिसमें समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आसियान सदस्य देश और गैर-आसियान देश शामिल होते हैं। EAMF, आसियान समुद्री मंच (AMF) पर आधारित है, जो आसियान के भीतर समुद्री सुरक्षा, सुरक्षा और सहयोग से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन इसे क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों के व्यापक समूह तक विस्तारित करता है।

भारत की सदस्यता:

• भारत EAMF का सदस्य है। भारत समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए EAMF में सक्रिय रूप से भाग लेता है, खासकर समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती से निपटने और इंडो-पैसिफिक में नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में।

EAMF का उद्देश्य है:

1. समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना: आसियान सदस्य देशों और बाहरी भागीदारों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, खासकर समुद्री डकैती, तस्करी और अन्य समुद्री अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में।
2. सहयोग को प्रोत्साहित करना: समुद्री क्षेत्रों में आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
3. नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना: अंतरराष्ट्रीय कानून, खासकर समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के अनुरूप समुद्री क्षेत्रों के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थन करना।
4. विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण करना: संवाद, क्षमता निर्माण पहल और संयुक्त अभ्यास के माध्यम से भाग लेने वाले देशों के बीच विश्वास बढ़ाना, एक स्थिर और सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना।

बैठकें: EAMF का आयोजन आसियान समुद्री मंच (AMF) के साथ-साथ वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह आसियान देशों और प्रमुख बाहरी भागीदारों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस को एक साथ लाता है।

आसियान प्लस थ्री (APT): आसियान प्लस थ्री एक क्षेत्रीय ढांचा है जिसमें दस आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ) सदस्य देशों के साथ-साथ तीन पूर्वी एशियाई देश: चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।

सदस्य: आसियान सदस्य देश: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम।

प्लस थ्री: चीन, जापान, दक्षिण कोरिया।

गठन: आसियान प्लस थ्री प्रक्रिया की शुरुआत 1997 में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के रूप में की गई थी, जो 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद पूर्वी एशियाई सहयोग की आवश्यकता से विकसित हुई थी।

उद्देश्य:

- आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना।
- आर्थिक एकीकरण और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, विशेष रूप से आर्थिक संकटों के मद्देनजर।
- खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करना।
- लोगों के बीच आदान-प्रदान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना।

मुख्य पहल:

- चियांग माई पहल: संकट के समय वित्तीय बाजारों को स्थिर करने के उद्देश्य से एक बहुपक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था।
- आसियान+3 आपातकालीन चावल भंडार: प्राकृतिक आपदाओं या खाद्य संकटों के मामले में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम।

महत्व: आसियान प्लस थ्री पूर्वी एशियाई एकीकरण और सहयोग को गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इसने एक अधिक सुसंगत क्षेत्रीय आर्थिक और राजनीतिक वातावरण को बढ़ावा दिया है और क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र बन गया है।

- **भारत** आसियान प्लस थ्री ढांचे का सदस्य **नहीं** है, लेकिन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और आसियान क्षेत्रीय फोरम जैसे अन्य मंचों के माध्यम से आसियान और इसके सदस्य राज्यों के साथ मजबूत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध बनाए रखता है।

ग्रीनवाशिंग दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ? कंपनियों को उनके उत्पादों या सेवाओं की पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति के बारे में झूठे या भ्रामक दावे करने से रोकने के लिए, केंद्र ने हाल ही में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो कंपनियों के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ अपने दावों को प्रमाणित करना अनिवार्य बनाते हैं।

ग्रीनवाशिंग या भ्रामक पर्यावरण दावों की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा जारी किए गए थे, जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है।

ग्रीनवाशिंग क्या है?

- हालाँकि इन दिशा-निर्देशों में ग्रीनवाशिंग शब्द का इस्तेमाल विज्ञापन के सीमित संदर्भ में किया गया है, लेकिन इसका दायरा बहुत व्यापक है। ग्रीनवाशिंग का मतलब कंपनियों, संगठनों या यहाँ तक कि देशों द्वारा अपनी **गतिविधियों, उत्पादों या सेवाओं के पर्यावरण**-अनुकूल या जलवायु-अनुकूल होने के बारे में संदिग्ध या अपुष्ट दावे करने की बढ़ती प्रवृत्ति से है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के कारण, निगमों और सरकारों पर अपनी गतिविधियों को इस तरह से करने का दबाव बढ़ रहा है जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। उनमें से कई के पास इस संबंध में पालन करने के लिए **कानूनी प्रतिबद्धताएँ** या लक्ष्य भी हैं।
- परिणामस्वरूप, कंपनियाँ और सरकारें अक्सर ऐसे दावे करती हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण, भ्रामक या कुछ मामलों में गलत होते हैं। 2015 का वोक्सवैगन घोटेला, जिसमें जर्मन कार कंपनी को अपने **कथित ग्रीन डीजल वाहनों** के उत्सर्जन परीक्षण में धोखाधड़ी करते हुए पाया गया था, ग्रीनवाशिंग के सुर्खियों में आने वाले उदाहरणों में से एक है। **शेल, बीपी और कोका कोला** सहित कई अन्य बड़ी कंपनियों पर ग्रीनवाशिंग के आरोप लगे हैं।

ग्रीनवाशिंग को रोकने के लिए विज्ञापन संबंधी दिशा-निर्देश क्या हैं?

- CCPA का अधिदेश उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है और इसलिए, इसके दिशा-निर्देश उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापनों में ग्रीनवाशिंग को रोकने तक सीमित हैं।
- वे ग्रीनवाशिंग को "किसी भी भ्रामक या भ्रामक अभ्यास" के रूप में परिभाषित करते हैं जो प्रासंगिक जानकारी को छिपाता है, छोड़ता है या छुपाता है, या अतिशयोक्ति करता है, या उत्पाद या सेवा के बारे में अस्पष्ट या निराधार पर्यावरणीय दावे करता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, भ्रामक शब्दों, प्रतीकों या छवियों का उपयोग, सकारात्मक पर्यावरणीय विशेषताओं पर जोर देते हुए नकारात्मक पहलुओं को कम करके या छिपाते हुए ग्रीनवाशिंग माना जाएगा।
- हालाँकि, वे "स्पष्ट अतिशयोक्ति" या "आडंबर" के उपयोग की अनुमति देते हैं, जो विज्ञापन व्यवसाय के लिए केंद्रीय है, अगर ये धोखाधड़ी या भ्रामक अभ्यास के बराबर नहीं हैं।
- अगर कोई कंपनी, उदाहरण के लिए, यह बयान देती है कि उसका विकास "टिकाऊ सिद्धांतों" पर आधारित है, तो इसे इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्यों के लिए भ्रामक पर्यावरणीय दावे के रूप में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कंपनी दावा करती है कि उसके सभी उत्पाद टिकाऊ तरीके से निर्मित किए जाते हैं, तो उसे ग्रीनवाशिंग के लिए जांचा जाएगा।
- इस प्रकार, किसी उत्पाद के लिए "स्वच्छ", "हरा", "पर्यावरण के अनुकूल", "ग्रह के लिए अच्छा", "क्रूरता-मुक्त", "कार्बन तटस्थ", "प्राकृतिक", "जैविक", "टिकाऊ", या इसी तरह के अन्य विवरण जैसे सामान्य शब्दों की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब कंपनी इन्हें सबूतों के साथ प्रमाणित करने में सक्षम हो। कंपनी को ऐसे विवरणों का विज्ञापन करते समय "पर्याप्त और सटीक" योग्यता और प्रकटीकरण का भी उपयोग करना होगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के बारे में:

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता शिकायतों को दूर करने के लिए की गई थी।

CCPA की संरचना:

अध्यक्ष: CCPA का नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त (अध्यक्ष) करता है।

सदस्य:

- दो अतिरिक्त आयुक्त हैं, एक माल के लिए और दूसरा सेवाओं के लिए, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भी नियुक्त किया जाता है।
- CCPA अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल कर सकता है।
- **सलाहकार परिषद:** CCPA में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मामलों पर सुझाव देने के लिए उपभोक्ता अधिकार, कानून और सार्वजनिक प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ एक सलाहकार परिषद हो सकती है।

CCPA की शक्तियाँ:

- CCPA उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है और अनुचित व्यापार प्रथाओं या भ्रामक विज्ञापनों की जाँच कर सकता है।
- यह प्राधिकरण के तहत **महानिदेशक (जांच)** को जाँच के लिए मामलों को भी संदर्भित कर सकता है।
- प्राधिकरण असुरक्षित वस्तुओं को वापस लेने या **भ्रामक विज्ञापनों** को वापस लेने के निर्देश जारी कर सकता है।
- यह किसी कंपनी को दोषपूर्ण या असुरक्षित पाए जाने पर सामान या सेवाओं की कीमत वापस करने का आदेश दे सकता है।
- सीसीपीए के पास भ्रामक विज्ञापनों के लिए व्यक्तियों या व्यवसायों पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।
- यह ऐसे विज्ञापनों के समर्थनकर्ता या प्रकाशक को भी जिम्मेदार ठहरा सकता है।
- सीसीपीए उन मामलों में **स्वप्रेरणा से (अपनी गति से)** कार्रवाई कर सकता है, जहां उसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या किसी अनुचित व्यापार व्यवहार का संदेह होता है।
- सीसीपीए ऐसे मामलों में **सामूहिक कार्रवाई मुकदमा** शुरू कर सकता है, जिसमें एक ही उत्पाद या सेवा से कई उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा हो।

मिओम्बो वन

चर्चा में क्यों ? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और इतालवी विकास सहयोग एजेंसी (एआईसीएस) ने हाल ही में मिओम्बो वन की सुरक्षा और मोजाम्बिक तथा जिम्बाब्वे के बीच सीमा क्षेत्र में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर मापुटो में हस्ताक्षर किए गए।

8 मिलियन डॉलर से कुछ अधिक मूल्य की इन परियोजनाओं को इटली द्वारा अफ्रीका के लिए **मैटेई योजना** के ढांचे के भीतर वित्त पोषित किया जाएगा। ये पहल खाद्य सुरक्षा को बढ़ाकर, आजीविका में सुधार करके और पर्यावरणीय तथा आर्थिक चुनौतियों के प्रति लचीलापन बढ़ाकर मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे के बीच सतत विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

पहली परियोजना, मिओम्बो वनों का एकीकृत सीमापार सतत प्रबंधन, का उद्देश्य मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे द्वारा साझा किए गए मिओम्बो वन के सतत उपयोग को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना और बढ़ावा देना है।

- यह वन ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो जलाऊ लकड़ी, भोजन और पानी जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करता है।
- परियोजना सतत आजीविका, जैव विविधता संरक्षण और समुदाय-आधारित प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- यह चयनित क्षेत्रों में 5,000 परिवारों को सीधे लाभान्वित करेगा, लैंगिक समानता और युवा भागीदारी को बढ़ावा देगा। यह पहल अगस्त 2022 में अपनाए गए **मियोम्बो वुडलैंड्स** के सतत और एकीकृत प्रबंधन पर **प्रोटोकॉल और मापुटो घोषणा (2022) के अनुरूप है।**

मियोम्बो के बारे में:

- मियोम्बो एक बायोम है जिसमें उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, बुशलैंड और सवाना शामिल हैं।
- इसमें चार जैव-क्षेत्र भी शामिल हैं और यह ग्रेटर ज़ाम्बेज़ी को बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है, जो सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय नदी घाटियों में से एक है।

मापुटो घोषणा (2022) के बारे में:

- यह अफ्रीका में कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के प्रयासों को मज़बूत करने के लिए अफ्रीकी देशों द्वारा की गई नई प्रतिबद्धता को संदर्भित करता है।
- यह पिछले घोषणापत्रों, खास तौर पर 2003 के मापुटो घोषणापत्र पर आधारित है, जिसमें पूरे महाद्वीप में कृषि को बढ़ावा देने और भुखमरी को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

स्कैम से बचो अभियान

चर्चा में क्यों? मेटा की यह पहल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), गृह मंत्रालय (MHA), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) जैसे प्रमुख मंत्रालयों के सहयोग से शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटना है, जो ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते मामलों को संबोधित करने और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है।

मुख्य तथ्य:

- 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता
- साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि, 2023 में 1.1 मिलियन मामले दर्ज किए गए

साइबर घोटालों के प्रकार:

- सोशल मीडिया घोटाला/डेटा घोटालानौकरी घोटाले/ऋण ऐप धोखाधड़ी/बैंकिंग धोखाधड़ी/ई-कॉमर्स धोखाधड़ी आदि:

मेटा क्या है?

- मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है।
- हाल ही में हुए साइबर घोटाले/हमले- डिजिटल गिरफ्तारी आदि।

सरकार और अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम।

- नया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023/भारत ने ऑनलाइन 'संदिग्ध रजिस्ट्री' शुरू की।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।
- डिजिटल ऋण के लिए RBI के दिशानिर्देश:
- जागरूकता अभियान: घोटाले से बचाओ/"साइबर सुरक्षित भारत"
- अवैध ऐप्स पर नकेल: 2023 में, ED ने ऐसे घोटालों से जुड़ी अरबों की संपत्ति को प्रीज कर दिया।
- CERT-In को मजबूत करना:

आगे की राह:

- मजबूत नियामक ढांचा:** विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिनटेक कंपनियों के लिए एक अधिक मजबूत नियामक ढांचा आवश्यक है। RBI और SEBI को धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल ऋण और निवेश प्लेटफॉर्म पर अपनी निगरानी को कड़ा करने की आवश्यकता है।

2. **एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी को ट्रैक करने के लिए प्रौद्योगिकी फर्मों, वित्तीय संस्थानों और दूरसंचार कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। और ऑनलाइन धोखाधड़ी का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करें।
3. **जन जागरूकता और डिजिटल साक्षरता:** जन जागरूकता अभियान और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों पर अधिक जोर देना आवश्यक है। नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम, सुरक्षित भुगतान विधियों और फ़िशिंग हमलों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल साक्षरता कम है।
4. **उन्नत साइबर सुरक्षा अवसंरचना का विकास:** उन्नत साइबर सुरक्षा अवसंरचना में निवेश, जैसे कि AI-आधारित खतरा पहचान प्रणाली, धोखाधड़ी को बढ़ने से पहले पहचानने और कम करने में मदद करेगी।
5. **वैश्विक सहयोग:** कई घोटालों की सीमा-पार प्रकृति को देखते हुए, भारत को अंतरराष्ट्रीय धोखेबाजों, विशेष रूप से चीन जैसे देशों से जुड़े लोगों को ट्रैक करने के लिए वैश्विक एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए।
6. **उपभोक्ता संरक्षण उपाय:** ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और वित्तीय सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र सहित अपने उपभोक्ता संरक्षण उपायों को मजबूत करना चाहिए।
7. **कानूनी सुधार:** ऑनलाइन धोखेबाजों पर सख्त दंड लगाने और त्वरित सुनिश्चित करने के लिए विशेष साइबर अपराध अदालतें बनाने के लिए साइबर कानूनों में सुधार होना चाहिए।

श्रम: वन स्टॉप सॉल्यूशन'

चर्चा में क्यों? ई-केंद्रीय श्रम मंत्री ने हाल ही में उन्नत 'ई-श्रम: वन स्टॉप सॉल्यूशन' पोर्टल लॉन्च किया है, जो असंगठित क्षेत्र के 300 मिलियन से अधिक श्रमिकों को स्वास्थ्य, पेंशन और भोजन सहित सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करेगा। हर दिन, लगभग 60,000 से 90,000 श्रमिक ई-श्रम प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ रहे हैं।

महत्व:

- यह प्लेटफ़ॉर्म एक पुल के रूप में कार्य करेगा, जो श्रमिकों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले कई लाभों से जोड़ेगा और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाएगा
- वन-स्टॉप सॉल्यूशन में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के डेटा को एक ही संग्रह में समेकित और एकीकृत करना शामिल है। यह पहल राज्य और जिलेवार छूटे हुए संभावित लाभार्थियों की पहचान करके योजनाओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी।

पोर्टल पर उपलब्ध योजनाएँ हैं:

- राशन कार्ड /पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), पीएमएवाई- शहरी, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल,

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच)।

ई-श्रम योजना के बारे में:

- इसे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, गिग श्रमिकों और अन्य सहित असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ और कल्याणकारी योजनाएँ प्रदान की जा सकें।
- ई-श्रम पोर्टल इन श्रमिकों को पंजीकरण करने और एक अद्वितीय ई-श्रम कार्ड प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल हैं और बीमा कवरेज जैसे लाभ प्राप्त करते हैं।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-II): दिल्ली में AQI 310 पर रहा - 'बहुत खराब' श्रेणी

चर्चा में क्यों ? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा कार्यान्वित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-II) का दूसरा चरण 22 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। CAQM के आदेश के अनुसार, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया।

21 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक, राष्ट्रीय राजधानी का **AQI 310 था, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** के अनुसार 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

- वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में, उप-समिति ने निर्णय लिया कि GRAP-बहुत खराब वायु गुणवत्ता के चरण II के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयाँ एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पहले से लागू चरण-I क्रियाओं के अलावा, सुबह 8:00 बजे से लागू की जाएंगी।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 22.10.2024 तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई)
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और आईआईटी मद्रास (आईआईटीएम) ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता 301-400 के बीच 'बहुत खराब' श्रेणी में रह सकती है।
- आईएमडी और आईआईटीएम ने कहा कि ऐसा प्रतिकूल मौसम संबंधी और जलवायु परिस्थितियों के साथ-साथ शांत हवाओं के कारण हो सकता है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के बारे में:

इसे 2017 में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सहयोग से लॉन्च किया गया था।

- GRAP एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना है, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में, जिसमें दिल्ली और आस-पास के क्षेत्र शामिल हैं।
- उद्देश्य: GRAP को प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता के विभिन्न स्तरों के आधार पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान दिल्ली में देखे गए गंभीर वायु प्रदूषण के दौरान।

GRAP की मुख्य विशेषताएँ:

मध्यम से खराब (AQI 101-300):

- प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए भारी जुर्माना।
- सड़कों पर मशीनीकृत सफाई और पानी का छिड़काव।

बहुत खराब (AQI 301-400):

- डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)।
- सार्वजनिक परिवहन की आवृत्ति में वृद्धि।

गंभीर (AQI 401-500):

- ईट भट्टों और हॉट मिक्स प्लांट को बंद करना।
- स्टोन क्रशर और पटाखों पर प्रतिबंध।
- गंभीर+ या आपातकालीन (AQI >500)
- स्कूल, कार्यालय और निर्माण गतिविधियाँ बंद हो सकती हैं।

लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर

चर्चा में क्यों? ई-पाकिस्तान के लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जिसका वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 394 है।

- इसके जवाब में, पंजाब सरकार ने स्मॉग के प्रभाव से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की योजना की घोषणा की है।
- AQI हवा में विभिन्न प्रदूषकों की सांद्रता को मापता है, जिसमें 100 से ऊपर की मात्रा को अस्वस्थ और 150 से ऊपर की मात्रा को "बहुत अस्वस्थ" माना जाता है।

स्मॉग संकट का मुख्य कारण:

- फसल अवशेष जलाने और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण

स्मॉग का प्रभाव:

- निवासियों में खांसी, सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और त्वचा संक्रमण सहित व्यापक स्वास्थ्य समस्याएं।
- मरियम नवाज की पंजाब सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक 'एंटी-स्मॉग स्कवाड' भी शुरू किया है।

स्मॉग क्या है? धुआँ और कोहरे का मिश्रण, स्मॉग तब होता है जब प्रदूषणकारी सूक्ष्म कण ठंडी, नम हवा के साथ मिलकर ज़मीन के करीब लटकते हैं, दृश्यता कम करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ पैदा करते हैं।

इसका दीर्घकालिक समाधान क्या है?

- सुपर सीडर का उपयोग
- विनियामक ढाँचे को मज़बूत करना
- वायु गुणवत्ता निगरानी
- स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
- ऊर्जा दक्षता
- सार्वजनिक परिवहन में सुधार
- जन जागरूकता - जैसे- एंटी-स्मॉग स्कॉड
- पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ ने स्मॉग के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के साथ "जलवायु कूटनीति" का आह्वान किया है।
- उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों पक्षों को सहयोग करना चाहिए, उन्होंने कहा कि भारत के पंजाब में पराली जलाने से हवा के प्रवाह के कारण पाकिस्तान प्रभावित होता है। "इस मुद्दे को भारत के साथ तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए।

जलवायु कूटनीति और हरित कूटनीति" क्या है?

जलवायु कूटनीति:

- जलवायु कूटनीति विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को संबोधित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वार्ता, समझौते और प्रयासों को संदर्भित करती है। इसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और लचीलापन बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए देशों, संगठनों और हितधारकों के बीच चर्चा शामिल है।

हरित कूटनीति:

- हरित कूटनीति एक व्यापक शब्द है जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कूटनीतिक प्रयासों को शामिल करता है। इसमें जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ जैव विविधता, प्रदूषण, संरक्षण और सतत संसाधन प्रबंधन जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।

छाया बेड़े (शैडो फ्लीट) /सुविधा के लिए ध्वज(फ्लैग ऑफ कन्वीनिएस (FoC)

चर्चा में क्यों ? रूस-यूक्रेन संघर्ष को कवर करते समय, कई पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने टैंकर जहाजों का वर्णन करने के लिए 'छाया बेड़े' शब्द का इस्तेमाल किया है जो रूसी कच्चे तेल या तेल उत्पादों को दूसरे देशों में ले जाते हैं। यह शब्द समुद्री लुटेरों जैसे जहाजों और अवैध, प्रतिबंधित पदार्थों का व्यापार करने वाले काल्पनिक मालिकों की छवि को दर्शाता है। भारत को एक छाया बेड़े के मेजबान के रूप में चित्रित किया गया है जो रूसी कच्चे तेल को 'धोखा' दे रहा है।

प्रतिबंधों को कैसे लागू किया जाता है?

- जब अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है, जैसा कि रूस के मामले में है, तो वह प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं, कंपनियों और व्यक्तियों की जांच शुरू करता है।
- अमेरिका में उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, पश्चिमी बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच वाले बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं और कभी-कभी उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है।
- रूसी तेल के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के अनुसार रूस अपना कच्चा तेल केवल **60 डॉलर प्रति बैरल** पर बेच सकता है। मौजूदा बाजार मूल्य कम से कम **15 डॉलर** अधिक हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रूस तेल की बिक्री से बहुत अधिक लाभ न कमाए और इसका उपयोग यूक्रेन में अपने युद्ध प्रयासों के लिए न करे।

वैश्विक शिपिंग की संरचना क्या है?

- वैश्विक शिपिंग उद्योग अत्यधिक विविधतापूर्ण है। यूनानियों के पास वैश्विक मर्चेट शिपिंग बेड़े का 20% हिस्सा है, जबकि चीन अब जापान को पार करके मर्चेट शिपिंग बेड़े के स्वामित्व के मामले में दूसरा अग्रणी देश बन गया है।
- अधिकांश जहाज चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में बनाए और मरम्मत किए जाते हैं। फिर भी, समुद्री बीमा, जहाज वित्त और वैश्विक शिपिंग नियम यू.के. और शेष यूरोप के इर्द-गिर्द घूमते हैं। इन लीवर के माध्यम से अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू करने की कोशिश की जाती है।

भारत के खिलाफ क्या आरोप है?

- प्रतिबंध लागू होने के तुरंत बाद, कई रूसी जहाजों ने भारतीय फर्मों के साथ गठजोड़ कर लिया। कई ने अपना आधार दुबई में बदल लिया, जहां भारतीयों की शिपिंग में मौजूदगी है। भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस), एक वर्गीकरण सोसायटी ने प्रमाणित किए जा रहे जहाजों की संख्या में वृद्धि देखी, जिससे छाया बेड़े में भारतीय भागीदारी के आरोपों को बल मिला।
- यह देखते हुए कि इसे रूसी शिपिंग संस्थाओं से जोड़ा गया है, आईआरएस ने कहा कि इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी एक जहाज की सुरक्षा है और इससे समझौता नहीं किया जाएगा।
- आईआरएस ने बताया कि उसे वास्तव में दुबई स्थित संस्थाओं द्वारा कई जहाजों को सुरक्षा-संबंधी वर्गीकरण सेवाएँ प्रदान करने के लिए कहा गया है। ये जहाज लाइबेरिया और साइप्रस के ध्वज प्रशासन के तहत पंजीकृत थे और उनमें से किसी पर भी रूसी झंडा नहीं था, आईआरएस ने बताया।
- 2015 में, जब ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो लगभग 160 जहाज, जिनमें से कई ईरानी तेल से व्यापारिक संबंध रखते थे, ने अपनी वर्गीकरण सोसायटी को कोरियाई शिपिंग रजिस्टर में बदल दिया - कोरिया एक अमेरिकी सहयोगी है। कभी-कभी किसी जहाज का नाम बदलने से प्रतिबंधों के साथ जुड़ाव को मिटाने में मदद मिल सकती है।

फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस (FoCs) और शैडो फ्लीट क्या हैं?

- वे शिपिंग उद्योग में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं, अक्सर समुद्री विनियमन, श्रम प्रथाओं और पर्यावरण अनुपालन के बारे में चर्चाओं में।

फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस (FoCs):

- फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस से तात्पर्य उस देश के झंडे के बजाय किसी विदेशी झंडे के तहत जहाज को पंजीकृत करने की प्रथा से है, जहां जहाज का स्वामित्व या संचालन होता है। यह प्रथा जहाज मालिकों को विदेशी देश में अधिक उदार विनियमन, कम करों और कम श्रम लागत का लाभ उठाने की अनुमति देती है।

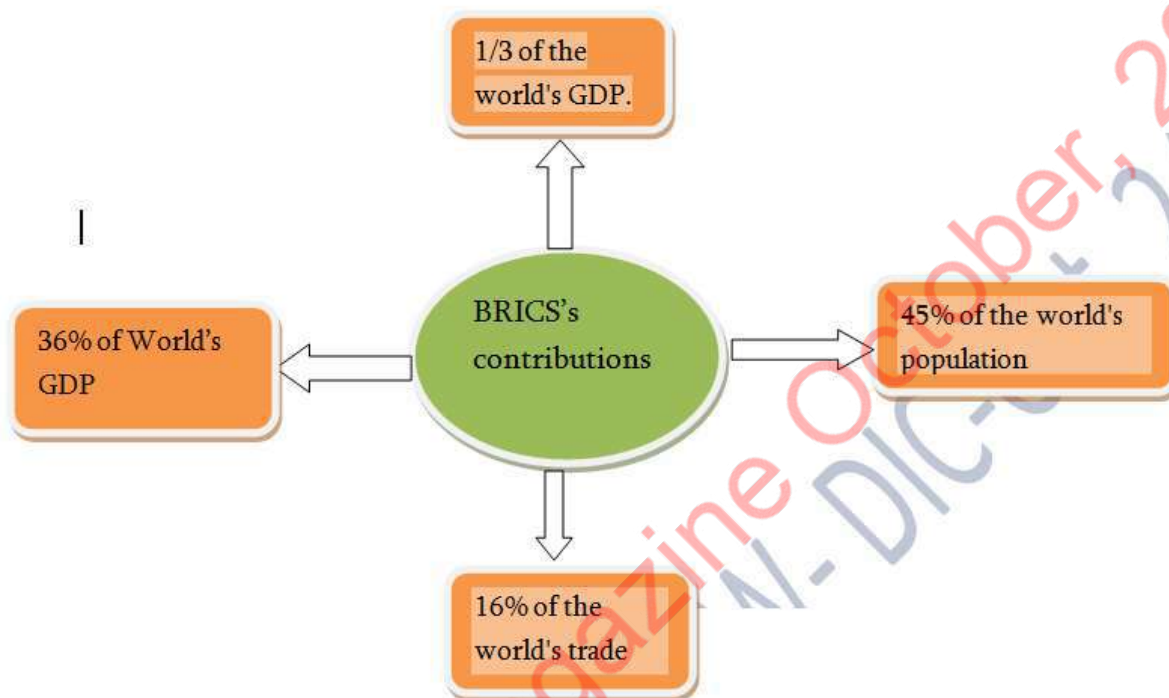
कज़ान घोषणा: 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024

चर्चा में क्यों? हाल ही में रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। इसमें न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य घोषणा:

- रूस ने स्विफ्ट के मुकाबले ब्रिक्स के नेतृत्व वाली भुगतान प्रणाली पर जोर दिया
- ब्रिक्स राष्ट्र ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज और ब्रिक्स (री)इंश्योरेंस कंपनी जैसी पहलों का पता लगाने पर सहमत हुए।

- शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स भागीदार देश श्रेणी के निर्माण का भी समर्थन किया गया, जो अन्य देशों को विभिन्न परियोजनाओं पर ब्रिक्स के साथ सहयोग करने की अनुमति देगा।
- टीका विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए **ब्रिक्स आरएंडडी वैक्सीन सेंटर** की घोषणा की गई।
- शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस बनाने की भारत की पहल को मान्यता दी गई



ब्रिक्स के बारे में:

- ब्रिक शब्द ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए गढ़ा था।
- **ब्राजील, रूस, भारत और ब्रिक** के संस्थापक देशों के साथ 2009 में स्थापित। बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया (ब्रिक्स)।
- ब्रिक्स का विस्तार: **अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और यूएई** ब्रिक्स में छह नए सदस्य हैं।

जैव विविधता अक्षुण्णता सूचकांक (BII)

चर्चा में क्यों? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएचएम) ने हाल ही में एक अध्ययन किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के अंदर जैव विविधता उनके बाहर की तुलना में अधिक तेज़ी से घट रही है।

- महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र (सीबीए) पारिस्थितिकी तंत्र और आर्द्रभूमि जैसे क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं - जिनमें से **22% संरक्षित हैं**

रिपोर्ट क्या कहती है?

- निष्कर्ष, जो चल रहे संरक्षण प्रथाओं के बारे में सवाल उठाते हैं, सुझाव देते हैं कि केवल अधिक क्षेत्रों को संरक्षित के रूप में नामित करने से "स्वतः ही जैव विविधता के लिए बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे"।
- यह नीति निर्माताओं और कानून के प्रवर्तकों के लिए "एक चेतावनी" है कि किसी क्षेत्र को केवल संरक्षित के रूप में नामित करना पर्याप्त नहीं था।
- सरकार और नीति निर्माताओं को यह जानने की जरूरत है कि यह केवल एक संख्या को हिट करने के बारे में नहीं है
- जैव विविधता अखंडता सूचकांक (BII) 2000 और 2020** के बीच वैश्विक स्तर पर 1.88 प्रतिशत अंकों से कम हो गया है।
- उन्होंने पाया कि "उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के भीतर जो संरक्षित नहीं थे, जैव विविधता में औसतन गिरावट आई थी **2000 से 2020 के बीच 1.9 प्रतिशत अंक और संरक्षित क्षेत्रों में 2.1 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है।**

गिरावट क्यों हो रही है?

- कई संरक्षित क्षेत्र पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि केवल कुछ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि पूर्ण "जैव विविधता अक्षुण्णता" प्राथमिकता नहीं है।
- संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक और खतरा तेल, गैस और खनन रियायतें हैं - सरकार द्वारा तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन करने वाली कंपनियों को दी गई भूमि। उदाहरण के लिए, **कोंकौती-डौली राष्ट्रीय उद्यान का 65% से अधिक हिस्सा**, जो कांगो गणराज्य में सबसे अधिक जैव विविधता वाले संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, तेल और गैस रियायतों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
- जलवायु संकट भी एक भूमिका निभाता है। अधिक लगातार और तीव्र सूखे और जंगल की आग ने संरक्षित क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, **ऑस्ट्रेलिया के कई राष्ट्रीय उद्यान**, जिन्हें अधिकारियों द्वारा सख्ती से संरक्षित किया गया है, **2019 में जंगली आग से नष्ट हो गए।**

आगे का रास्ता क्या है?

- यह निर्धारित करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट विश्लेषण की आवश्यकता है कि ये परिदृश्य क्यों बिगड़ रहे हैं।
- सुरक्षा उपाय पर्याप्त रूप से कड़े नहीं हैं।
- देशों को 30x30 (2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागरों को संरक्षण के तहत रखने के लिए जैव विविधता COP15 में देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता) पर अपना ध्यान जारी रखने की आवश्यकता है, जिसे कम नहीं किया जाना चाहिए।
- उन्हें बस इसमें और अधिक लाने की आवश्यकता है, और वास्तव में उस भूमि को संरक्षित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो उन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को प्रदान करती है।

जैव विविधता अक्षुण्णता सूचकांक (BII) के बारे में:

- इसे लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी किया जाता है। BII एक मीट्रिक है जिसका उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि मानवीय गतिविधियों के बावजूद किसी क्षेत्र में जैव विविधता किस हद तक अक्षुण्ण बनी हुई है।
- यह प्रभाव-पूर्व स्तरों के सापेक्ष मूल रूप से मौजूद प्रजातियों की औसत बहुतायत को मापता है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जैव विविधता पर भूमि उपयोग, वनों की कटाई, कृषि और शहरीकरण के प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- BII एक प्रतिशत स्कोर प्रदान करता है, जो दर्शाता है कि किसी क्षेत्र की मूल जैव विविधता कितनी बची हुई है। उदाहरण के लिए, 90% का BII बताता है कि 90% प्रजातियाँ बरकरार हैं, जबकि 50% से कम स्कोर महत्वपूर्ण जैव विविधता हानि का संकेत दे सकता है।

प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (NHM) के बारे में:

- यह लंदन में स्थित है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है, जो प्राकृतिक इतिहास और जैव विविधता के अध्ययन के लिए समर्पित है।
- NHM में नमूनों का एक व्यापक संग्रह है और यह वैज्ञानिक अनुसंधान, सार्वजनिक शिक्षा और संरक्षण वकालत के लिए संसाधन प्रदान करता है।
- संग्रहालय के संग्रह और अनुसंधान पृथ्वी की प्राकृतिक विविधता को समझने और जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों का समर्थन करते हैं।

सरको या 'सुसाइड पॉड'

चर्चा में क्यों? स्विटजरलैंड पुलिस ने हाल ही में एक 64 वर्षीय अमेरिकी महिला की 'सुसाइड पॉड' द्वारा की गई मौत में शामिल होने के आरोप में कम से कम चार लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला, जिसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, कथित तौर पर वर्षों से ऑटोइम्यून स्थिति से पीड़ित थी।

- इस घटना ने विवादास्पद सरको पॉड पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे डॉ. फिलिप निश्चके द्वारा इंजीनियर किया गया था, जो एक ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक हैं जिन्होंने इच्छामृत्यु समर्थक समूह एक्जिट इंटरनेशनल की स्थापना की थी।
- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सहायता प्राप्त मृत्यु और इच्छामृत्यु की नैतिकता के बारे में भी सवाल उठाता है।

इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त मृत्यु क्या है?

- इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त मृत्यु दोनों ही ऐसे तरीके हैं, जिनमें कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना जीवन समाप्त करना चुन सकता है।
- इच्छामृत्यु व्यक्ति को घातक दवा देने के लिए चिकित्सक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। इच्छामृत्यु दो तरह की हो सकती है - स्वैच्छिक, जहाँ रोगी अपनी स्पष्ट सहमति देता है, और अनैच्छिक, जब वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि वे कोमा में होते हैं।
- दूसरी ओर, सहायता प्राप्त मृत्यु, घातक पदार्थ के स्व-प्रशासन पर निर्भर करती है, जिसमें चिकित्सा भागीदारी केवल दवा की खरीद तक सीमित होती है। इसका अर्थ है जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने में मदद करना, और यह निर्धारित नहीं करता है कि वह व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है।

सरको पॉड क्या है?

- प्राचीन राजघरानों को दफनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के ताबूत, सरको के नाम पर, एक ताबूत के आकार की, एयर-टाइट मशीन है जिसे एक्जिट इंटरनेशनल द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
- पहली बार 2019 में बनाया गया, सरको पॉड में एक 3D-प्रिंटेड डिटेचेबल कैप्सूल होता है जिसे लिक्विड नाइट्रोजन के कनस्टर के साथ एक स्टैंड पर रखा जाता है। इसके अंदर लेटा हुआ व्यक्ति मरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक बटन दबा सकता है, जिससे इसके अंदर की हवा नाइट्रोजन गैस से भर जाती है।
- इस डिवाइस को नीदरलैंड में निश्चके और डच इंजीनियर एलेक्स बैनिंक ने 12 वर्षों में डिज़ाइन और निर्मित किया है और इसके अनुसंधान और विकास पर लगभग €650,000 (\$725,000) की लागत आई है। भविष्य के पॉड्स की लागत लगभग €15,000 होने का अनुमान है और इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसे कौन एक्सेस कर सकता है?

- यह पॉड हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, और इच्छुक उम्मीदवारों को पहले एक ऑनलाइन मानसिक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। "यदि वे पास हो जाते हैं, तो उन्हें एक सरको डिवाइस तक पहुंच कोड प्राप्त होता है जो 24 घंटे काम करता है। कोड दर्ज करने और अतिरिक्त पुष्टि दिए जाने के बाद, जनरेटर में तरल नाइट्रोजन जारी किया जाता है, जिससे कैप्सूल में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम हो जाता है। एक मिनट के भीतर, उपयोगकर्ता बेहोश हो जाता है; कुछ ही समय बाद मृत्यु हो जाती है।
- यह डिवाइस पोर्टेबल है और इसे जहाँ चाहें वहाँ ले जाया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य

ग्रेन ग्रिफ़ गिरोह

ग्रेन ग्रिफ़ गिरोह हैती में एक सशस्त्र आपराधिक समूह है जो व्यापक हिंसा के लिए ज़िम्मेदार है, खास तौर पर आर्टिबोनाइट क्षेत्र में। हाल ही में, गिरोह ने पोंट-सोंडे इलाके में एक क्रूर हमला किया, जिसमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए और हज़ारों लोग विस्थापित हो गए। गिरोह ने क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है, नागरिकों को निशाना बनाया है, घरों और वाहनों को जला दिया है और समुदाय के दैनिक जीवन को बुरी तरह से बाधित किया है।

- हैती सरकार और राष्ट्रीय पुलिस ने गिरोह की गतिविधियों को रोकने के लिए संघर्ष किया है, जिसके कारण महत्वपूर्ण आंतरिक विस्थापन और असुरक्षा बढ़ गई है। ग्रेन ग्रिफ़ के नेता लक्सन एलन को मानवाधिकारों के हनन और गिरोह से संबंधित हिंसा में शामिल होने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

अदिति 2.0 और DISC 12 पहल

भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में डेफकनेक्ट 4.0 में दो प्रमुख पहलों- ADITI 2.0 और DISC 12- का शुभारंभ किया है। इन पहलों का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करके और नए विचारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

ADITI 2.0 क्या है?

- ADITI 2.0 19 प्रौद्योगिकी चुनौतियों पर केंद्रित है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सैन्य संचार प्रणाली और एंटी-ड्रोन तकनीक जैसे उन्नत क्षेत्रों को कवर करती हैं।
- सरकार इन चुनौतियों का सफल समाधान निकालने वालों को ₹25 करोड़ तक का अनुदान दे रही है।

DISC 12 क्या है?

- DISC 12, 12वीं डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चुनौती, **41 नई प्रौद्योगिकी चुनौतियों को पेश** करती है। इन चुनौतियों में मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में नवाचार शामिल हैं।

- कार्यक्रम में मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट (MIRA) पहल भी शामिल है, जो विशेष रूप से सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है। शीर्ष विचारों को ₹1.50 करोड़ तक का अनुदान मिल सकता है।

iDEX पहल:

- रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) पहल, जो अटल इनोवेशन मिशन के साथ काम करती है, नई रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में स्टार्ट-अप और छोटे व्यवसायों (MSME) का समर्थन करती है।
- iDEX कंपनियों को प्रोटोटाइप बनाने और अंततः इन उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करता है। अपनी शुरुआत के बाद से, iDEX ने 9,000 से अधिक आवेदनों की समीक्षा की है और रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 450 से अधिक कंपनियों के साथ भागीदारी की है।

2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार

- स्वीडिश अकादमी ने दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना है। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला हैं। वह पूर्व राष्ट्रपति किम डे-जंग के बाद नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई हैं। राष्ट्रपति किम डे-जंग को 2000 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- हान कांग को 10 दिसंबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम, स्वीडन में एक समारोह में 11 मिलियन क्रोनर पुरस्कार मिलेगा।

नोबेल पुरस्कार विजेता हान कांग के बारे में-

- 2016 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी द्वारा उनके "गहन काव्यात्मक गद्य" के लिए चुना गया है जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है।
- उनके उपन्यास 'द वेजिटेरियन' ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और इस कृति के लिए उन्हें 2016 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला था।

महिला साहित्य पुरस्कार विजेता-

- हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली 18वीं महिला हैं।
- साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला स्वीडन की सेल्मा लेगरलोफ़ थीं जिन्हें यह सम्मान 1909 में मिला था।

साहित्य में नोबेल पुरस्कार-

- नोबेल फाउंडेशन ने अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार, 1900 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया।
- फ्रांस के सुली प्रुधोमे 1901 में साहित्य पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे।

साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय-

- रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार (1913) प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे।
- वह यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं।

मात्सिगुएनका समुदाय

- पेरू के मात्सिगुएनका समुदाय के एक स्वदेशी नेता गेराडो केइमारी एनरिक की हाल ही में हुई हत्या ने स्वदेशी भूमि अधिकारों की अधिक मज़बूत सुरक्षा की मांग को और तेज़ कर दिया है।
- मात्सिगुएनका समुदाय एक स्वदेशी समूह है जो मुख्य रूप से पेरू के अमेज़ॉन में स्थित है, विशेष रूप से माद्रे डी डिओस के क्षेत्र और कुस्को के कुछ हिस्सों में।



ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन

ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए शुरू की गई पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को संबोधित करना और शहर में पर्यावरण शासन में सुधार करना है।

ग्रीन वॉर रूम:

उद्देश्य: दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित ग्रीन वॉर रूम, वायु गुणवत्ता और अन्य पर्यावरणीय चिंताओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर के रूप में कार्य करता है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है।

संचालन:

- वॉर रूम दिल्ली भर में विभिन्न प्रदूषण निगरानी प्रणालियों से वास्तविक समय का डेटा एकत्र करता है और प्रदूषण स्पाइक्स पर तत्काल प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है।
- यह वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल और कचरे को जलाने जैसे प्रमुख प्रदूषण स्रोतों की निगरानी करता है।
- वॉर रूम वायु गुणवत्ता के स्तर को ट्रैक करने और नागरिकों और अधिकारियों को अलर्ट प्रदान करने के लिए उन्नत तकनीक और सॉफ्टवेयर से लैस है।
- **ग्रीन दिल्ली ऐप** को दिल्ली सरकार द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था ताकि नागरिकों को पर्यावरणीय मुद्दों, विशेष रूप से वायु प्रदूषण को संबोधित करने में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार (COFER) की मुद्रा संरचना

यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा बनाए रखा जाने वाला एक सांख्यिकीय डेटाबेस है जो देशों के विदेशी मुद्रा भंडार की मुद्रा संरचना को ट्रैक करता है। ये भंडार केंद्रीय बैंकों और मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न मुद्राओं में रखी गई संपत्तियां हैं, जिनका उपयोग राष्ट्रीय मुद्रा का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

COFER के मुख्य पहलू:

भंडार की संरचना: COFER मुख्य रूप से विभिन्न प्रमुख मुद्राओं में रखे गए भंडार की रिपोर्ट करता है:

- अमेरिकी डॉलर (USD)

- यूरो (EUR)
- जापानी येन (JPY)
- ब्रिटिश पाउंड (GBP)
- चीनी रेनमिनबी (CNY)
- स्विस फ्रैंक (CHF)

बिजनेस ईमेल समझौता (BEC) क्या है?

बिजनेस ईमेल समझौता (BEC) एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जो ईमेल के ज़रिए होता है। BEC हमले में, हमलावर पीड़ित को धोखा देकर कुछ कार्रवाई करने के लिए ईमेल संदेश को गलत बताता है - सबसे अधिक बार, हमलावर द्वारा नियंत्रित खाते या स्थान पर पैसे ट्रांसफर करता है। BEC हमले कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ईमेल-आधारित हमलों के अन्य प्रकारों से भिन्न होते हैं:

1. उनमें मैलवेयर, दुर्भावनापूर्ण लिंक या ईमेल अटैचमेंट नहीं होते हैं
2. वे संगठनों के भीतर विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित करते हैं
3. वे इच्छित पीड़ित के लिए वैयक्तिकृत होते हैं और अक्सर संबंधित संगठन के अग्रिम शोध को शामिल करते हैं

BEC हमले विशेष रूप से खतरनाक होते हैं क्योंकि उनमें मैलवेयर, दुर्भावनापूर्ण लिंक, खतरनाक ईमेल अटैचमेंट या अन्य तत्व नहीं होते हैं जिन्हें ईमेल सुरक्षा फ़िल्टर पहचान सकता है। BEC हमले में उपयोग किए जाने वाले ईमेल में आमतौर पर टेक्स्ट के अलावा कुछ नहीं होता है, जो हमलावरों को सामान्य ईमेल ट्रैफ़िक के भीतर उन्हें छिपाने में मदद करता है।

मूल खाते और किराए के खाते

म्यूल अकाउंट:

- अपराधियों द्वारा अवैध धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए म्यूल अकाउंट का उपयोग किया जाता है, ताकि मूल और गंतव्य को छिपाया जा सके। अक्सर, खाताधारक (या "म्यूल ") को उन लेन-देन की अवैध प्रकृति के बारे में पता हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जिनकी वे सुविधा प्रदान करने में मदद कर रहे हैं।
- म्यूल खाते आम तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, फ़िशिंग और व्यावसायिक ईमेल समझौता (बीईसी) धोखाधड़ी जैसी योजनाओं का हिस्सा होते हैं।
- म्यूल या तो अनजाने में भागीदार हो सकते हैं (यह सोचकर कि वे वैध काम कर रहे हैं) या सहभागी भागीदार (यह जानते हुए कि वे किसी अपराध में सहायता कर रहे हैं)।

किराए के खाते:

- दूसरी ओर, किराए के खातों में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो जानबूझकर अपने बैंक खातों तक पहुँच किसी और को "किराए पर" देते हैं, अक्सर शुल्क के बदले में।
- किराए के खाते की योजना में, खाताधारक को आमतौर पर पता होता है कि वे किसी और को पहुँच दे रहे हैं, हालाँकि उन्हें हमेशा शामिल अवैध गतिविधियों की बारीकियों का पता नहीं हो सकता है।
- किराए के खातों का इस्तेमाल **धोखाधड़ी और लॉन्ड्रिंग** में भी किया जाता है, लेकिन अक्सर ये जानबूझकर किए जाते हैं। ये किराएदार के लिए भी जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि ये पहुँच प्रदान करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

मुख्य अंतर:

- मूल खाताधारक अनजाने में भागीदार हो सकते हैं, जबकि किराए के खाताधारक आमतौर पर जानते हैं कि वे अपना खाता किराए पर दे रहे हैं। संचालन: खचर खातों को आम तौर पर खाताधारक की भर्ती के बाद किसी तीसरे पक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि किराए के खाते खाताधारक द्वारा अस्थायी उपयोग के लिए जानबूझकर प्रदान किए जाते हैं।

उदाहरण:

मूल अकाउंट: कोई व्यक्ति किसी नौकरी के विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देता है, जिसमें धन हस्तांतरित करने के लिए आसान आय की पेशकश की जाती है, इस बात से अनजान कि यह धन फ़िशिंग घोटालों से आता है।

किराए का खाता:

किसी व्यक्ति से मासिक शुल्क के बदले में किसी को अपना खाता इस्तेमाल करने देने का प्रस्ताव दिया जाता है। वे पहुँच की अनुमति देते हैं, यह जानते हुए कि तीसरा पक्ष अज्ञात उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करेगा। दोनों प्रकारों को अक्सर बैंकों द्वारा **संभावित मनी लॉन्ड्रिंग** और धोखाधड़ी के लिए चिह्नित किया जाता है, क्योंकि इनका उपयोग आपराधिक योजनाओं में धन की आवाजाही को छिपाने के लिए किया जाता है।
